दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 24 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 57

महत्वपूर्ण एवं खास

पाक सेना की नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों व गांवों पर गोलाबारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास अग्रिम चौकियों और गांवों पर अकारण गोलाबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुँहतोड़ जवाब दिया। यहां नई दिल्ली में एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि नियंत्रण रेखा की रखवाली करने वाली भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंदूकों पर विराम लगाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और सुंदरबनी सेक्टर में दोनों पक्षों के बीच सीमा पार से गोलीबारी अंतिम रिपोर्ट मिलने तक जारी थी। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने बिना कोई उकसावे के सुबह करीब 11.30 बजे छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर और मोर्टार दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी गोलाबारी में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

एम के दास झारखंड विस के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग ने मृणाल कांति दास (आईपीएस 1977 सेवानिवृत्त) झारखंड राज्य विधान सभा चुनाव 2019 के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने झारखंड में वामपंथी उग्रवाद के कारण कानून व्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। एम के दास अपनी नई जिम्मेदारी संभाले के लिए आज रांची पहुंचेंगे और पुलिस बल की तैनाती एवं सुरक्षा संबंधी अन्य मुद्दों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि दास मणिपुर पुलिस के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था।

जैव-प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो-इंडिया समिट 2019 संपन्न

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत का पहला सबसे बड़ा जैव-प्रौद्योगिकी हितधारकों का समूह- ग्लोबल बायो-इंडिया (जीबीआई) समिट, 2019 आज यहां संपन्न हुआ। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने अपने सार्वजनिक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ मिलकर किया। इस आयोजन के लिए अन्य भागीदारों में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉलेड एंटरप्राइजेज (एबीएलई) और इन्वेस्ट इंडिया शामिल थे।

भारतीय मूल के व्यक्ति को कोर्ट ने बलात्कार का दोषी ठहराया

न्यू यॉर्क। न्यू यॉर्क में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक महिला के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया है। ऐक्टिंग चीफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन रेयान ने कहा कि पेंसिल्वेनिया के अशोक सिंह (58) को दो सप्ताह तक चले मुकदमे के बाद बलात्कार और गैरकानूनी ढंग से बंधक बनाने का दोषी पाया गया। उसे अगले महीने सजा सुनाई जाएगी और उसे 25 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मुकदमे के अनुसार, दिसंबर 2015 में सिंह ने पीड़िता से मुलाकात की थी, जो किराए के एक अपार्टमेंट की तलाश में थी और तब इस व्यक्ति ने उस महिला को रहने के लिए जगह खोजने में मदद करने की पेशकश की थी। चार दिन बाद सिंह ने 40 वर्षीय महिला को बुलाया और उसे बताया कि उसे एक जगह मिल गई है और उसे तुरंत वहां जाना होगा। बाद में वह खाना और शराब लेकर उसके अपार्टमेंट में गया। क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक, पीड़िता ने जब सिंह के साथ शराब पीने से इनकार कर दिया, तो वह गुस्से में आ गया और उसके साथ बलात्कार किया। जब वह सो गया तो पीड़िता अपार्टमेंट से बाहर निकली और मदद के लिए अपने एक दोस्त से संपर्क किया।

2022 में भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ और 2047 में 100वीं वर्षगांठ मनाएगा: पीएम मोदी

» प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के 50वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। राज्यपालों का 50वां वार्षिक सम्मेलन आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग ले रहे है जिनमें पहली बार पदभार संभाले वाले 17 राज्यपाल/उपराज्यपाल भी शामिल हैं। साथ ही सम्मेलन में नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जल शक्ति मंत्री उपस्थित थे।

उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए 1949 से शुरू हुए इस सम्मेलन के लंबे इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान 50वें संस्करण के इस सम्मेलन को पिछले सम्मेलनों की उपलब्धियों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अनोखा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघीय ढांचे को साकार करने में राज्यपाल पद की विशेष भूमिका है। यह सम्मेलन राज्यपालों और उपराज्यपालों के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के साथ-साथ प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट एवं विविध आवश्यकताओं और उनके अनुकूल सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने का अवसर प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रशासनिक ढ़ाचे के कारण केंद्र शासित प्रदेश विकास के मोर्चे पर आदर्श स्थापित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि 2022 में भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ और 2047 में 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी को देश के लोगों के करीब लाने और उन्हें सही राह दिखाने में राज्यपाल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हम भारतीय संविधान के लागू होने की 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। ऐसे में राज्यपालों और राज्य सरकारों को भी भारतीय संविधान में विभिन्न सेवा पहलुओं को उजागर करने की दिशा में काम करना चाहिए, विशेष रूप से नागरिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में। इससे सही मायने में सभी की भागीदारी वाला शासन स्थापित करने में मदद मिलेगी।

मोदी ने कहा कि इस साल हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे है। इसलिए राज्यपाल एवं उपराज्यपाल इस अवसर का उपयोग गांधीवादी विचारों और मूल्यों की प्रासंगिकता बताने के लिए कर सकते हैं जो हमारे संविधान के एक महत्वपूर्ण आधार हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में अपनी भूमिकाओं में राज्यपाल हमारे युवाओं के बीच राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को विकसित करने और उन्हें अधिक से अधिक उपलब्धियों की ओर प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं।

उन्होंने अपने संबोधन के अंत में राज्यपालों और उपराज्यपालों से अनुरोध किया कि वे आम लोगों की जरूरतों पर ध्यान देने और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए करें। प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से आग्रह किया कि वे अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं और युवाओं सहित कमजोर तबकों के उत्थान की दिशा में काम करें। इसके लिए वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के अलावा वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वनयन पर ध्यान दे सकते हैं।

महाराष्ट्र की अदालत ने मानहानि के मामले में खारिज की राहुल की अर्जी

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की अर्जियां शनिवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने आरएसएस के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि संबंधी शिकायत रद्द करने का अनुरोध किया था.

अब राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी दोनों इस मामले में सुनवाई का सामना करेंगे.

आरएसएस कार्यकर्ता और वकील ध्रुतिमान जोशी ने इस संबंध में एक शिकायत दायर करके पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित रूप से संघ से जोड़ने वाली टिप्पणी के लिए गांधी और येचुरी के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू करने का अनुरोध किया था. 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

वहीं दिल्ली की एक अदालत ने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक शिकायत शनिवार को खारिज कर दी.

अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कार्रवाई रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जिसमें कहा गया था कि गांधी के खिलाफ कोई ''संज्ञेय अपराध'' नहीं बनता.

एक दिसंबर से वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल हाईवे से अपने गंतव्य पर जाने वाले सभी प्रकार के चार पहिया वाहनों के लिए आगामी 1 दिसम्बर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव में सभी वाहनों को फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। सरकार 100 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन हासिल करने के लिए यह कदम उठा रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 1 दिसंबर से टोल प्लाजाओं को ई-टोल संग्रह से जोड़ना अनिवार्य है। इसलिए जिन वाहनों पर अभी फोस्टैग नहीं लगे हैं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो से गुजरने वाले वाहनों पर फास्टैग फ्री में लगाने की योजना शुरू की है जो एक दिसंबर तक होगी और उसके बाद वाहन मालिकों को खुद ही फास्टैग खरीदना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि एक दिसंबर से जिस वाहन पर फास्टैग नहीं होगा, उसे दोगुना टोल राशि जमा करने के बाद टोल पार कराया जाएगा। एक दिसंबर से देशभर के सभी टोल प्लाजा फास्टैग से लैस हो जाएंगे। देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर कुल 527 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से एक कैश लेन को छोड़कर 380 टोल प्लाजा के सभी लेन फास्टैग से लैस हो गए हैं और बाकी इसी तर्ज पर एक दिसंबर तक सभी लाइनें फास्टैग से लैस हो जाएंगी। फास्टैग प्रीपेड खाता खोलने के लिए बैंक की ऑनलाइन फास्टैग एप्लिकेशन वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह खुल जाएगा।

क्या होता है फास्टैग

फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिक्रेशन का इस्तेमाल होता है। वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगने वाले विशेष प्रकार के श्टैगश् के कारण जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा के नजदीक आएगी तो वहां लगा सेंसर वाहन फास्टैग को ट्रैक कर लेगा। जैसे ही टोल प्लाजा पर आप पहुंचेंगे, वहां पर आपके फास्टैग खाते से निर्धारित शुल्क अपने आप कट जाएगा।

सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर कश्मीर में कट्टरपंथी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कश्मीर में जबरदस्त चौकसी के बावजूद कट्टरपंथ फल-फूल रहा है। युवाओं का ब्रेनवाश करने में जुटे मौलवियों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथ लगातार चुनौती बना हुआ है। दक्षिण कश्मीर इसका गढ़ बना है जहां बाहर से आए कई मौलवी एजेंसियों की रडार पर हैं।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कट्टरपंथ का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसके आगोश में आए स्थानीय युवा बंदूक थामने से नहीं हिचकिचाते। सुरक्षा बलों ने लगातार ग्रामीणों के बीच कट्टरपंथ के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया है, लेकिन ग्रामीणों का डर समाप्त करने में वे सफल नहीं हुए हैं। दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में कट्टरपंथी ताकतों,आतंकियों और अलगाववादियों का गठजोड़ सक्रिय है।

सुरक्षा बल से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद की तरह ही कट्टरपंथ के खिलाफ सघन अभियान की जरूरत महसूस की जा रही है। क्योंकि कट्टरपंथ के जरिये ही युवाओं को आतंकी बनाने का अभियान चल रहा है। इसके लिए धार्मिक प्रतिष्ठानों का सहारा लिया जा रहा है। धारा 370 समाप्त करने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं का ब्रेनवाश करने की घटनाओं का संज्ञान लिया गया है। सुरक्षा बल से जुड़े एक अन्य अधिकारी के मुताबिक उन जगहों की मैपिंग की गई है जहां कट्टरपंथी प्रचार- प्रसार की साजिश चल रही है। पुलवामा और शोपियां के कई गांवों में सुरक्षा बलों ने कट्टरपंथ के शिकार युवाओं के घर वालों को आगाह भी किया है। सूत्रों ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में गुमराह युवक कट्टरपंथी ताकतों की गिरफ्त में हैं। इनपर नजर रखी जा रही है। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय आतंकियों की भर्ती को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है।

कांग्रेस-एनसीपी का कुर्सी के लिए मैच फिक्सिंग कैसे: भाजपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। फडणवीस के शपथ ग्रहण के बाद विपक्ष की ओर से हो रही बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि भाजपा और शिवसेना ने जब बहुमत प्राप्त किया तो ये भाजपा गठबंधन की नैतिक और चुनावी विजय थी। चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना किसके इशारे पर उत्तेजक हो गई थी? महाराष्ट्र के उलटफेर पर बीजेपी की तरह से बड़ी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत पर प्रेस काफ्रेंस करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने जब बहुमत प्राप्त किया तो ये भाजपा गठबंधन की नैतिक और चुनावी विजय थी। चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना किसके इशारे पर उत्तेजक हो गई थी? शरद पवार और कांग्रेस ने परिणाम के बाद बयान दिया था कि हमें विपक्ष में बैठने का जनमत मिला है। तो ये विपक्ष में बैठने का जनमत कुर्सी के लिए मैच फिक्सिंग कैसे हो गया था।

रविशंकर प्रसादन ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैनडेट था भाजपा और शिवसेना, लेकिन बड़ी पार्टी थी भाजपा और मुख्यमंत्री का मैनडेट था योग्य और ईमानदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फ्डणवीस के लिए था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाने वालों को निशाने पर लेते हुए पूछा कि कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की हो गई है। जब शिवसेना स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर अपनी 30 साल की दोस्ती तोड़कर अपने घोर विरोधियों का दामन थाम ले तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या?

आतंकवादी मौतों में आई 15 फीसद की कमी!

नई दिल्ली (आरएनएस)। आतंक विरोधी अभियान और खुफिया एजेंसियों की चुस्ती से आतंकवाद का फन कुचलने की दिशा में दुनिया चल पड़ी है।

ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2017 की तुलना में 2018 में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 15 फीसद की कमी आई है। आतंक के मामले में सुधार का यह लगातार चौथा वर्ष है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि आतंक प्रभावित देशों का दायरा बढ़कर 71 हो गया है। 2002 के बाद से दक्षिण एशिया आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जबकि मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं। यूरोप में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 70 फीसद की गिरावट आई है।

अफगानिस्तान के अधिकांश प्रांतों के साथ-साथ तजाकिस्तान में भी तालिबान की गतिविधियों में वृद्धि हुई। 71 फीसद की वृद्धि के साथ 2018 में तालिबान ने किसी भी अन्य आतंकवादी समूह की तुलना में सबसे ज्यादा 6,103 जानें लीं। आइएस को पीछे छोड़ते हुए यह दुनिया का सबसे घातक आतंकवादी समूह बना है। यह समूह 2018 में वैश्विक स्तर पर सभी आतंकवादी मौतों में 38 फीसद के लिए जिम्मेदार है। 2018 में आतंकवाद से 7,379 लोगों की जान जाने के साथ अफगानिस्तान इस सूची में पहले स्थान पर है। 2017 के मुकाबले यहां मौतों में 46 फीसद की वृद्धि हुई। आइएस की गतिविधियों में आई गिरावटरू सीरिया और इराक में सक्रिय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा ली गई जानों में 69 फीसद की गिरावट देखी गई। लंबे समय से आंतक से पीड़ित इराक में आतंकवादी संबंधी मौतों में सबसे बड़ी कमी देखी गई।

महाराष्ट्र में भाजपा को 168 विधायकों का समर्थन!

» मोदी सरकार में मंत्री बनेंगी सुप्रिया सुले

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा ने शनिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में देवेन्द्र फ्डनवीस-अजित पवार सरकार के पास विधानसभा में कम से कम 168 विधायकों का समर्थन है और यह सरकार पूरे 5 साल स्थिरता के साथ राज्य की सेवा करेगी। इस बीच मुंबई में भाजपा एक प्रवक्ता ने दावा किया कि सरकार के साथ राकांपा के सभी विधायक हैं।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के नेता रामदास अठावले ने दावा किया कि राकांपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार में शामिल होगी तथा सुप्रिया सुले मंत्री बनेंगी। भाजपा के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने यहां कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के पास पूरा बहुमत है। विधानसभा के पटल में मुख्यमंत्री आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। बहुमत के आंकड़े पर उन्होंने भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के हवाले से दावा किया कि सरकार के समर्थन में कम से कम 168 विधायकों का समर्थन हासिल है। रिपोर्टों के अनुसार अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 22 विधायकों के साथ बैठक करके भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का फैसला किया। पर बहुमत के लिए शिवसेना के विधायकों के भी टूटने के बारे में पूछे जाने पर इस्लाम ने कहा कि वे सटीक आंकड़ों के बारे में नहीं बता सकते हैं, पर दावा करते हैं कि सदन में कम से कम 168 विधायक सरकार के समर्थन में हैं।

इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के नेता रामदास अठावले ने दावा किया कि राकांपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार में शामिल होगी तथा सुप्रिया सुले मंत्री बनेंगी। उधर महाराष्ट्र से भाजपा के सूत्रों ने कहा कि अजित पवार को चूंकि राकांपा के विधायक दल का नेता चुना जा चुका था इसलिए दलबदल कानून उनके फैसले पर लागू नहीं होगा बल्कि उनके साथ नहीं आने वाले विधायकों को संभवतरू अनुशासन के मामले का सामना करना पड़े।